नैफेड द्वारा सेना को घटिया दालों की पूर्ति

439. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) सेना को दालों की पूर्ति कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले दिनों सेना को घटिया दालों की ऊंचे दामों पर पूर्ति की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने नैफेड के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्दाकर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते।

दूरदर्शन कार्यक्रम संबंधी जोशी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

440. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 3 मई, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 398 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय की संचार माध्यम सलाहकार समिति ने दूरदर्शन कार्यक्रमों के संबंध में जोशी समिति के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर कोई निर्णय ले लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी नहीं।

सिनेमाघरों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा ऋण

441. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा सिनेमाघरों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों को दिए गए ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन ऋणों के संबंध में कुछ अयनिमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल): (क) विभिन्न राज्यों में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम वर्ष 1983–84 और 1984–85 के दौरान मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिये**)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्यों में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वर्ष 1983–84 और 1984–85 के दौरान मंजूर किए गए ऋण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन	1983–84		1984–85	
		उन थियेटरों की संख्या जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया	मंजूर राशि (रुपये लाखों में)	उन थियेटरों की संख्या जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया	मंजूर राशि (रुपये लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	7.50	6	43.75
2.	असम	1	7.50	—	—
3.	बिहार	—	—	2	13.70
4.	गुजरात	—	—	1	7.50
5.	कर्णाटक	4	24.85	4	19.70
6.	केरल	2	10.50	—	—
7	मध्य प्रदेश	4	28.50	6	41.50
8.	महाराष्ट्र	1	7.50	6	40.20
9.	मेघालय	—	—	1	7.50
10.	तमिलनाडु	1	7.50	4	21.35
11.	उत्तर प्रदेश	3	18.00	3	22.50
12.	पश्चिम बंगाल	1	77.60	1	7.50
		18	119.35	34	225.20

Special Housing Registration Scheme for Retiring Persons

442. SHRI F. M. KHAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the DDA's advertisement regarding special housing registration scheme, 1985 which appeared in various news-papers on 9th July, 1985;

(b) if so, what is the criteria adopted for fixing such an annual income ceilings; and

(c) whether Government propose to raise the ceiling after calculating the income of Government servants?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) Yes, Sir.